नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 058
दि. 27.06.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'रामभक्तों की अग्निपरीक्षा मत लो, आस्था से खिलवाड़ किया तो खैर नहीं', एफआईआर के बाद देवरिया में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में विपक्ष पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की SIT रिपोर्ट के बाद तीखा हमला बोला।

(जीएनएस)।

देवरिया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट आने और इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दोटूक शब्दों में कहा कि सरकार ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि इस मामले में 'दूध का दूध और पानी का पानी' होकर रहेगा। जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने अयोध्या और भगवान श्रीराम पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि

अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो और श्रीराम की मयार्दा का पालन करना सीखो। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज इस मामले को लेकर उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी मंशा कभी अच्छी नहीं रही। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और अदालत में हलफनामा देकर कहा था कि 'राम हुए ही नहीं'। ये लोग हमेशा से अयोध्या को नकारते रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि आज सवाल उठाने वाला दूसरा पक्ष वो है जो कभी 'जय श्रीराम' का नारा लगाने वालों पर लाठियां और गोलियां चलवाता था। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि तुम बताओगे हमें आस्था क्या होती है? ये वो लोग हैं जो रामनवमी पर दंगे करवाते थे और कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे।

कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को सिर्फ लूटा ही नहीं, बल्कि बेरहमी से नोचा था। ऐसे लोग आज ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं।

सबूत है तो रक्ळ को सौंपें, राजनीति न करें

सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं फिर कहता हूं कि रामभक्तों की अग्निपरीक्षा मत लो और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर उनके पास इस मामले में कोई भी वास्तविक प्रमाण या सबूत है, तो उसे मीडिया में उछालने और राजनीति करने के बजाय सीधे एसआईटी के सामने पेश करें, जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।

जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी 200 लोगों की समस्याएं, तुरंत कार्रवाई का दिया भरोसा

गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याएं सुनी, जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करिए. सरकार सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.

(जीएनएस)।

गोरखपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की हर समस्या का शीघ्र समाधान कराएं. लोगों की शिकायतों को संवेदनशीलता से लेकर संतुष्टिप्रद निस्तारण सुनिश्चित कराने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करिए. सरकार सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.

प्रार्थना पत्रों पर तुरंत एक्शन

जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे लोगों तक सीएम स्वयं चलकर पहुंचे और सबकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को पास में खड़े अधिकारियों को हस्तगत कर समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा.

जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

जनता दर्शन में हर बार की तरह कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. हृदय रोग से पीड़ित एक महिला से उन्होंने कहा कि इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाएगी. सीएम योगी ने जमीन कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में त्वरित व कड़े कदम उठाए जाएं. जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथरस और आगरा में होगा दौरा, करेंगे विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

(जीएनएस)।

हाथरस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जून को हाथरस और आगरा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी हाथरस में कुल एक घंटा 20 मिनट रुकेंगे। इस दौरान वे विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी सुबह 10 बजे लखनऊ स्थित पांच, कालिदास मार्ग से कार द्वारा रवाना होंगे।

सुबह 10:20 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचकर राजकीय वायुयान से उड़ान भरेंगे। सुबह 11:00 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:05 बजे राजकीय हेलीकाप्टर से हाथरस के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:20 बजे सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, हाथरस स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। 11:25 बजे कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे।

सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्य कार्यक्रम होगा। यहां सीएम योगी विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम समाप्त कर 12:40 बजे हेलीकाप्टर से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:55 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचकर 1:00 बजे आयुक्त सभागार, आगरा पहुंचेंगे।

यहां दोपहर 1:00 से 2:15 तक लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल के पुराने व नए कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2:15 से 2:45 तक आरक्षित समय है। इसके बाद 2:45 से 3:45 तक मंडलीय विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की हाई-लेवल समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 3:45 बजे आयुक्त सभागार से खेरिया एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे।

शाम 4:00 बजे राजकीय वायुयान से लखनऊ रवाना होंगे। शाम 4:40 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचकर 5:05 बजे पांच, कालिदास मार्ग, लखनऊ वापस लौटेंगे।प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा और तैयारियां तेज कर दी हैं। सलेमपुर में कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है।

पंजाब : राज्य के विकास-इंजन की बिजली कैसे हो रही गुल? सिस्टमैटिक फेल्योर के चक्कर में बिजली व्यवस्था में संघर्ष से जूझता

(जीएनएस)।

दशकों तक पंजाब ने भारत की हरित क्रांति को ऊर्जा दी, लेकिन आज स्थिति यह है कि राज्य खुद अपनी बिजली व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। गर्मियों में बिजली की मांग अमूमन चरम पर पहुंचती है और इसी दौरान धान की खेती का मौसम भी शुरू होता है।

पिछले कुछ वर्षों से पंजाब गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है। राज्य के थर्मल पावर प्लांटों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रिड से महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता बढ़ गई है, किसान अनियमित बिजली आपूर्ति की शिकायत कर रहे हैं, कर्मचारी आंदोलनरत हैं और उद्योग बढ़ती लागत को लेकर चिंतित हैं।

हालांकि मौजूदा संकट आम आदमी पार्टी (अअढ) सरकार के कार्यकाल में सामने आया है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। वर्षों तक सुधारों में देरी, जर्जर बुनियादी ढांचा, बढ़ता वित्तीय दबाव और विभिन्न सरकारों के दौरान प्रशासनिक सुस्ती ने पंजाब के बिजली क्षेत्र को धीरे-धीरे कमजोर किया है। नतीजा यह है कि राज्य की बिजली व्यवस्था ऐसे समय में सबसे अधिक कमजोर दिखाई दे रही है, जब पंजाब की अर्थव्यवस्था को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

पंजाब की बिजली व्यवस्था को उस समय बड़ा झटका लगा, जब राज्य संचालित ताप विद्युत संयंत्रों की छह इकाइयां एक साथ आउट ऑफ सर्विस हो गईं। इससे राज्य की उपलब्ध उत्पादन क्षमता में अनुमानतः1,800 मेगावाट से अधिक की कमी आ गई, जबकि यह वर्ष के सबसे अधिक बिजली मांग वाले दौरों में से एक था। इस कमी को पूरा करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (ढरढउछ) को राष्ट्रीय बिजली एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदनी पड़ी।

बिजली एक्सचेंज से खरीदी गई बिजली की लागत राज्य के अपने ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन की तुलना में काफी अधिक होती है। इससे पहले से वित्तीय दबाव झेल रही ढरढउछ पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा संकट के दौरान ढरढउछ को कुछ मौकों पर लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट तक की दर से बिजली खरीदनी पड़ी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृषि के सबसे महत्वपूर्ण मौसम के दौरान पंजाब की बिजली व्यवस्था इतनी असुरक्षित स्थिति में क्यों पहुंच गई? यदि यह केवल लापरवाही का परिणाम है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

इस संकट का सबसे बड़ा प्रतीक लेहरा मोहब्बत स्थित गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट बनकर सामने आया। राज्य के सबसे बड़े सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों में शामिल इस 920 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट की चारों इकाइयां हाल ही में बंद हो गईं। बाद में इनमें से एक इकाई को दोबारा चालू किए जाने की जानकारी सामने आई।

पंजाब सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंदी के पीछे फ्लाई ऐश का अत्यधिक जमाव और तकनीकी खराबियां प्रमुख कारण थीं। वहीं, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मरम्मत और बहाली का कार्य भी प्रभावित हुआ।

पावर प्लांट की स्थिति एक दिन में खराब नहीं होती। इस तरह की तकनीकी विफलताएं सामान्यतः वर्षों तक रखरखाव में कमी, समय पर आधुनिकीकरण न होने और परिसंपत्तियों के कमजोर प्रबंधन का परिणाम होती हैं। पंजाब के पुराने होते ताप विद्युत संयंत्र काफी समय से भारी मेंटिनेंस और अधुनिकीकरण की डिमांड कर रहे थे लेकिन विभिन्न सरकारें समय रहते इनके रिनोवेशन की दिशा में अपेक्षित गति से निवेश नहीं कर सकीं।

रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र की दो इकाइयां 30 वर्ष से अधिक समय तक संचालन के बाद बंद की गईं, जबकि कई अन्य इकाइयां या तो 25 वर्ष की सामान्य आर्थिक आयु पार कर चुकी हैं अथवा उसके करीब पहुंच चुकी हैं।

इमेज बचाने में लगे खान सर, ओखला में हो रही थी कौन सी प्लानिंग? राकेश यादव ने खोल दी सारी पोल, वीडियो वायरल

बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद

में अब एक और नया मोड़ आ गया है। खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद के बीच चल रहे विवाद के बीच अब शिक्षक राकेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में राकेश यादव ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली के ओखला में होने वाली एक बैठक में बुलाया गया था।

चंदा चोरी में एफआईआर दिखावा, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश : केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दौरे पर हैं, उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किए और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे छोटे कर्मचारी कर सकते हैं.

(जीएनएस)।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन किए. दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में दर्ज की गई FIR महज एक दिखावा और छलावा है.

अरविंद केजरीवाल ने घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा, "इतने बड़े घोटाले को इतने लंबे समय तक केवल जूनियर स्तर के कर्मचारी अकेले अंजाम नहीं दे सकते थे. यह पूरी तरह से साफ है कि इस भ्रष्टाचार की कड़ियां और तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं. इस मामले में असली प्रभावशाली

लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा दोष निचले स्तर के कर्मचारियों के सिर मढ़ा जा रहा है."

भगवान राम के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की बात कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमने भगवान राम के दर्शन किए और मंदिर में हुए इस इतने बड़े घोटाले को लेकर प्रभु से प्रार्थना की है, जिन्होंने भी यह पाप किया है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें भगवान राम कठोर से कठोर सजा दें."

केजरीवाल के साथ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, बता दें कि एक दिन पहले ही संजय सिंह लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने जमीनों की खरीद में भी भेदभाव किया है. उनका कहना है कि राम मंदिर के पास की जमीने सस्ते दामों में खरीदा गया और जो जमीनें दूर थीं उन्हें महंगे दामों पर खरीदा गया. उनका आरोप है कि ट्रस्ट के करीबियों को फायदा पहुंचाया गया है.

केजरीवाल राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- 'चंपत राय ने PM को हिसाब देने से मना कर दिया. इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की. ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि PM भी उनके सामने मजबूर हैं?

और दूसरी ओर SIT छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला कर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है.

लोकतंत्र सेनानियों को तीर्थयात्रा कराएगी सरकार, सीएम मोहन बोले- उनके संघर्ष से मजबूत हुआ भारत का लोकतंत्र

मध्य प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक विशेष तीर्थयात्रा ट्रेन की घोषणा करता है, जिसमें दो दिन का मुफ्त विश्राम गृह आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और स्मृति परियोजनाएँ शामिल हैं। यह आपातकाल काल और उसके बाद उनके योगदान का सम्मान करेगा।

(जीएनएस)।

मध्यप्रदेश सरकार अब लोकतंत्र सेनानियों को तीर्थयात्रा कराने के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष की वजह से ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन पाया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार, 95 वर्षीय शांति लाल संघवी और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का अभिनंदन किया गया। इस दौरान आपातकाल पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में बंद कर दिया जाता था। "न वकील, न अपील, न दलील" की स्थिति थी। परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों ने संघर्ष जारी रखा।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की लड़ाई देश की आजादी की दूसरी लड़ाई के समान थी। उन्हीं के संघर्ष के कारण आज लोकतंत्र सुरक्षित है और गरीब परिवार से निकलकर कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।

'मन कर रहा आत्महत्या कर लें', निशांत कुमार पर भड़के पीएमसीएच के प्रिंसिपल

पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने पद से हटाए जाने के बाद मीडिया के सामने अपना दर्द खुलकर बयां किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई ने उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है और उनका मन आत्महत्या करने तक का हो रहा है। डॉ. सिंह ने दावा किया कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उस दिन वह जलने की घटना के कारण अस्पताल नहीं जा सके। उन्होंने अपने शरीर पर जले हुए निशान भी दिखाए और सरकार पर बिना पक्ष सुने कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

लखनऊ में थम नहीं रहा 'अग्नि तांडव': 2 दिन में 2 संस्थानों में आग; 15 मौतों के बाद एक्सपर्ट ने बताई आगजनी की सबसे बड़ी वजह!

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार सुबह कानपुर रोड स्थित लोकबंधु अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सेंटर में आग लग गई. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ. जिस समय आग लगी, उस वक्त सेंटर में चार कर्मचारी मौजूद थे. हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया. समय रहते हैं यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह बड़ी आग की घटना हो सकती थी.

वहीं, इससे पहले 23 जून को ठाकुरगंज स्थित इरम कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय में आग लगी थी. उस घटना के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने भी बताया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद कार्यालय में रखे कागज और दस्तावेज उसकी चपेट में आ गए, जिससे आग ने गंभीर रूप धारण कर लिया. हालांकि घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया था. राहत की बात की है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

चीफ फायर ऑफिसर अंकुश

मित्तल ने बताया कि दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी मिली थी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आज की घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. बता दें कि इससे पहले 22 तारीख को अलीगंज क्षेत्र में भयानक अग्निकांड की घटना हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और आठ दर्जन लोग घायल हुए थे. उसके बाद राजधानी में अवैध रूप से संचालित तमाम कोचिंग संस्थान, होटल व ऑफिस को सीज किया गया है.

घटनाओं को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के 90% मामले शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं. इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में लगाए जाने वाले उपकरणों और घर में अर्थिंग की सही व्यवस्था की जाए. एक्सपर्ट देवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई घटना ना हो, इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से नियम भी निर्धारित किए गए हैं. कमर्शियल बिल्डिंगों और औद्योगिक क्षेत्रों में मानकों के तहत वायरिंग और एमसीबी लगाने के नियम हैं.

उन्होंने कहा कि परिसर में ट्रांसफार्मर और अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से बिजली का कनेक्शन देने से पहले एनओसी लेने की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है. एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और बिना जमीनी सत्यापन के ही बिल्डिंग को एनओसी मिल जाती है. ऐसे में यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि बिल्डिंग में मानकों के अनुसार बिजली के उपकरण लगे हैं या नहीं.

बिना जांच के बिजली विभाग इन बिल्डिंगों को बिजली का कनेक्शन दे देता है. ऐसे में कई बार लोड बढ़ने की वजह से वायर हीट हो जाते हैं और मानकों के अनुरूप एमसीबी न लगी होने से वह ट्रिप नहीं करती है, जिससे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं होती हैं और यही शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बाद में बड़ी आग का रूप ले लेती हैं.

वीडियो कॉल पर बेटी की विदाई देख थमी पिता की धड़कन, लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे लालबाबू

(जीएनएस)।

सोनबरसा (सीतामढ़ी)। कहते हैं एक पिता के जीवन का सबसे बड़ा और भावुक क्षण वह होता है, जब वह अपनी लाडली का कन्यादान करता है। अपनी पाई-पाई जोड़कर बेटी को रानी की तरह विदा करने का ख्वाब हर बाप देखता है।

सोनबरसा बस स्टैंड के रहने वाले लालबाबू महतो की आंखों में भी अपनी सबसे छोटी बेटी निधि के लिए यही अरमान तैर रहे थे। बुधवार की रात निधि के हाथ पीले हुए, घर में शहनाइयां गूंजीं, लेकिन नियति की लिखी स्क्रिप्ट इतनी क्रूर थी कि जिसे सुनकर पूरा इलाका सिसक उठा।

इधर बेटी की डोली उठी, और उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ के एक अस्पताल में वीडियो कॉल पर यह विदाई देख रहे पिता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।

नम आंखें और स्क्रीन पर 'वरमाला'

लालबाबू महतो सालों तक बस में कप्तानी (कंडक्टरी) कर अपने परिवार का पेट पालते रहे। तीन बेटों और दो बेटियों के इस भरे-पूरे परिवार में सबसे छोटी बेटी निधि की शादी को लेकर वो बेहद उत्साहित थे।

तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन शादी से ठीक तीन दिन पहले अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आनन-फानन में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके साथ पत्नी मीनू देवी और बेटा राजेश भी लखनऊ चले गए।

घर पर सिसकियां थीं, लेकिन लालबाबू की ही जिद थी कि बेटी की शादी तय तारीख पर ही हो। बुधवार की रात सीतामढ़ी में विवाह की रस्में शुरू हुईं।

लखनऊ के आईसीयू बेड पर लेटे लालबाबू के सामने मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी। वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपनी लाडली को दुल्हन बनते देखा। जब निधि ने दूल्हे को वरमाला पहनाई, तो अस्पताल के बेड पर बेबस पड़े पिता की आंखें खुशी और लाचारी के आंसुओं से छलक उठीं।

जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए भी एक पिता की सांसें सिर्फ इसलिए अटकी थीं, ताकि वह अपनी लाडली को विदा होते देख सके।

आंसुओं के साथ थम गईं पिता की सांसें

गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। विवाह संपन्न हो चुका था और अब निधि की विदाई की बेला थी। मायके से पैर भारी कर जैसे ही निधि डोली (गाड़ी) में बैठी, लखनऊ के अस्पताल में वीडियो कॉल की स्क्रीन पर लालबाबू महतो फफक कर रो पड़े।

उधर बेटी बाबुल का घर छोड़ रही थी, इधर पिता इस नश्वर संसार को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। दिल को झकझोर देने वाली बात यह रही कि जैसे ही निधि की विदाई का वीडियो कॉल कटा, उसके कुछ ही मिनटों बाद लालबाबू महतो की धड़कनें हमेशा के लिए शांत हो गईं।

निधि के ससुराल पहुंचते ही पिता के निधन की खबर आ गई। जिस घर से कुछ देर पहले मंगलगीत गाकर बेटी को विदा किया गया था, वहां अब चित्कार गूंज रही थी।

लाडली की डोली उठने का इंतजार शायद लालबाबू की आखिरी सांसें भी कर रही थीं, और फर्ज पूरा होते ही वो अनंत यात्रा पर निकल गए।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा, ट्रेलर से टकराई बस, 2 की मौत, 25 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस द्वारा ट्रेलर में टक्कर मारी गई. हादसे में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का भयानक कहर देखा गया है. थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 63 के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डबल डेकर स्लीपर बस के अगले हिस्से को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 60 यात्रियों से भरी एक निजी डबल डेकर स्लीपर बस को गोरखपुर से चंडीगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा था. जैसे ही बस को नगला खंगर इलाके में लाया गया, तभी उसे अचानक आगे चल रहे

एक ट्रेलर (ट्रक) में पीछे से टकराते हुए देखा गया. शुरूआती जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के दौरान बस चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन से नियंत्रण खो दिया गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाले गए यात्री

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा (वढएकऊअ) की रेस्क्यू टीमों द्वारा एम्बुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया गया. पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बस की खिड़कियों और क्षतिग्रस्त मलबे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती

हादसे में घायल हुए 25 यात्रियों को तत्काल शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इनमें से 5 यात्रियों की हालत बेहद नाजुक पाई गई, जिसके चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है. बाकी बचे यात्रियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है.

चालक और सह-चालक के शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम

इस संबंध में जानकारी देते हुए सिरसागंज की सीओ चंचल त्यागी द्वारा बताया गया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्ति बस के चालक और सह-चालक (कंडक्टर) हैं. पुलिस द्वारा दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है. फिलहाल, पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है.

लखनऊ में शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 3.27 करोड़ की ठगी, मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

लखनऊ। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने ठेकेदार से से 3.27 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जालसाज युवती ने खुद को यूएस की ट्रेडिंग कंपनी का अधिकारी बताकर फंसाया। ट्रेडिंग कराकर डीमैट अकाउंट में करीब दस करोड़ का मुनाफा दिखाया गया।

विड्राल पर टैक्स समेत अन्य मदों के नाम पर रुपये जमा कराकर उन्हें ब्लाक कर दिया गया। एडीसीपी क्राइम किरन यादव के आदेश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

अलीगंज सेक्टर-एन निवासी निजी फर्म के मालिक दीपक अग्रवाल जल निगम के ठेकेदार हैं। अक्टूबर 2025 में दीपक ने फेसबुक पर एक युवती से बातचीत शुरू की।

बातचीत के दौरान जालसाज ने व्यापार के बारे में पूछा और खुद को डिजिटल गोल्ड मिरेकल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बताया। उक्तदीपक ने 25 नवंबर को 40 हजार रुपये का निवेश कर ट्रेडिंग की। कुछ दिन बाद डीमैट अकाउंट में दस लाख यूएस

डालर (9.65 करोड़) का मुनाफा दिखाया गया।

यौमे आशूरा पर 'या हुसैन' 'या अब्बास' के नारों से गुंजा लखनऊ

आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले उन्हें याद कर, मातम कर रहे हैं

(जीएनएस)।

लखनऊ/सिद्धार्थनगर/बरेलीः राजधानी लखनऊ में नाज़िम अली इमामबाड़े से शुक्रवार को यौमे आशूरा का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया. जुलूस में हजारों की तादाद में अजादार शामिल हुए. इस दौरान "या हुसैन", "या सकीना", "या अब्बास" और "या मौला अली" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. सिद्धार्थनगर में भी मोहर्रम का पर्व बड़े ही अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया गया. हजरत इमाम हुसैन की याद में आजादारों ने भव्य जुलूस निकाला और मातम किया. बरेली के बहेड़ी नगर में मोहर्रम के अवसर पर ताजियों की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित किए जाने के बाद, सभी ताजिए को इमामबाड़ों में ही रखे गए. जुलूस की नेतृत मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद ने की.

ईटीवी भारत से बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जब हजरत इमाम हुसैन से पूछा गया कि वह किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने किसी मुस्लिम देश का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का नाम लिया था. उन्होंने कहा कि "हिंदुस्तान से हमें अपनी वतन की खुशबू आती है."

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादात है. झांसी की रानी के नाम का ताज़िया, महाराजा बनारस के नाम का ताज़िया और कई हिंदू राजाओं के नाम से आज भी ताज़िए रखे जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने 'इमाम हुसैन' शीर्षक से कर्बला पर पुस्तक लिखी, जो गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल है.

मौलाना ने कहा कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले उन्हें याद कर, मातम कर रहे हैं. लखनऊ की अवाम भी सड़कों पर

उतरकर "या हुसैन", "या अली" के नारे लगाते हुए कर्बला तक जाएंगे, जहां ताज़िए दफन किए जाएंगे. जुलूस के दौरान कुछ बच्चों के हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई की तस्वीरें भी दिखाई दीं.

प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद इस बार सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं कराया गया, जबकि, हर साल ऐसा किया जाता था. उन्होंने कहा कि सड़कें इतनी गर्म हैं कि लोगों के पैरों में छाले पड़ रहे हैं. इसे उन्होंने प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया.

फिरोजाबाद में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी द्वारा ताज़ियों को इंची टेप से नापे जाने के मामले पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और यह मुख्यमंत्री के निदेर्शों की भी अवहेलना है.

वहीं, मौलाना सैफ अब्बास ने ईटीवी भारत से कहा कि इंसानियत की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी और अपने परिवार की कुबार्नी दी थी. उसी कुबार्नी की याद में दुनिया भर के लोग आज सड़कों पर निकलते हैं.

उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के इमाम हुसैन को याद करते हैं. मौलाना ने कहा कि जिस तरीके से ताजिए को इंची टेप से नापा जा रहा है, इस तरीके से कावड़ यात्रा में भी इंची टेप लेकर, क्या यह पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरेंगे.

मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि दुनिया भर में लोग अपने बच्चों का नाम हुसैन रखते हैं, कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चे भी जंजीरी मातम कर रहे हैं. एक मां अपने बच्चे की उंगली कटने पर भी तड़प उठती है, लेकिन यहां बच्चे जंजीरी मातम करते हैं और जब उनके कपड़े खून से भीग जाते हैं. तो उनकी माएं इसे इमाम हुसैन की मोहब्बत और अकीदत का प्रतीक मानती हैं.

मौलाना सैफ ने कहा कि भीषण गर्मी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वे कर्बला के उस मैदान को याद करते हैं जहां हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने शहादत दी थी. उन्होंने कहा कि जुलूस की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है. शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस नाज़िम अली इमामबाड़े से करीब तीन किलोमीटर दूर कर्बला तालकटोरा की ओर बढ़ा है.

जुलूस में इस बार मेवे से तैयार किया गया एक अनोखा अलम भी आकर्षण का केंद्र रहा. करीब 50 किलोग्राम मेवों से तैयार इस अलम में मखाना, खजूर, छुहारा, बादाम, अंजीर और नारियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कर्बला तालकटोरा ले जाया गया है. इसके अलावा चांदी के अलम भी जुलूस में शामिल है. गुलाब के फूलों से सजे जुलूस में बड़ी संख्या में युवा नौहा पढ़ते और मातम करते हुए कर्बला की ओर बढ़ते दिखाई दिए.

अकबरी गेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां भारी संख्या में पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात हैं. मीनारा मस्जिद पर सुन्नी समुदाय का पारंपरिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जबकि शिया समुदाय का जुलूस अकबरी गेट से होकर कर्बला तालकटोरा पहुंचा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अकबरी गेट पर बड़ा पर्दा भी लगाया और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा.

सिद्धार्थनगर में इमाम हुसैन की याद में निकाला गया जुलूसः वहीं, सिद्धार्थनगर में मोहर्रम का पर्व बड़े ही अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया गया. उपनगर हल्लौर में श्रद्धालुओं ने भव्य जुलूस निकाला और हजरत इमाम हुसैन (र.अ.) की शहादत को याद करते हुए मातम किया. जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए. मातम करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि पूरी दुनिया में अमन व शांति कायम रहे, इसी उद्देश्य से हजरत इमाम हुसैन ने कर्बला के मैदान में अन्याय व जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपनी जान की कुबार्नी दे दी.

बरेली में ताजिए को इमामबाड़ों में ही रखे गएः बरेली के बहेड़ी नगर में मोहर्रम के अवसर पर ताजियों की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित किए जाने के बाद, नगर प्रमुख ताजिए जुलूस में शामिल नहीं हुए, सभी ताजिए को इमामबाड़ों में ही रखे गए, जिससे हर वर्ष लगने वाला नैनीताल रोड का मेला भी नहीं लग सका.

लखनऊ में 3 जुलाई से शुरू होगा 'यूपी आम महोत्सव', किसानों को कमाई का मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और किसानों को बेहतर विपणन अवसर प्रदान करना है।

(जीएनएस)।

मैनपुरी। प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसल आम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और किसानों को बेहतर विपणन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन तीन से पांच जुलाई तक लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। उद्यान विभाग ने जिले के प्रगतिशील आम उत्पादकों से महोत्सव में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है।

जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि महोत्सव में प्रदेश की उत्कृष्ट और व्यावसायिक आम की

विभिन्न किस्मों के साथ आम से तैयार प्रसंस्कृत उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

किसानों को मिलेगा नए अवसर तलाशने का मौका

कार्यक्रम के दौरान किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों के बीच खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित होंगी, जिससे किसानों को बाजार से जुड़ने और नए अवसर तलाशने का मौका मिलेगा।

उन्होंने बताया कि आम से बने उत्पाद, आकर्षक पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए किसानों को अपने आम के नमूने दो जुलाई सुबह 10 बजे तक लखनऊ भेजने होंगे। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले आमों को पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही किसान अपने उत्पादों की बिक्री भी कर सकेंगे।

लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशासी अभियंता के सस्पेंशन पर बिजली संगठनों ने किया प्रदर्शन

संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड की जांच में पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता पर की गई निलंबन की कार्रवाई पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दुखद घटना के लिए वास्तविक जिम्मेदारियों की निष्पक्ष जांच किए बिना अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) को निलंबित करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण, तथ्यहीन और बलि का बकरा बनाने की कार्रवाई है.

संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मांग की है

कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे का कहना है कि यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया है कि संबंधित भवन में विद्युत सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं थे और भवन का आवश्यक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी नहीं कराया गया था.

एसआईटी जांच के दौरान विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके कि भवन का विद्युत सुरक्षा ऑडिट कब किया गया था या घटना से पूर्व भवन की विद्युत सुरक्षा की जांच कब की गई थी? यह स्थिति स्पष्ट रूप से विद्युत सुरक्षा निदेशालय और अन्य संबंधित एजेंसियों की गंभीर लापरवाही को दशार्ती है.

संघर्ष समिति ने कहा कि अगर किसी भवन में विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया, विद्युत सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ. अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं और संबंधित विभागों ने समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया तो इन गंभीर कमियों की जिम्मेदारी निर्धारित किए बिना सिर्फ विद्युत वितरण निगम के एक अभियंता को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता.

संघर्ष समिति ने कहा कि निलंबन आदेश में स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसर का विद्युत भार वर्ष 2016 में विधिवत रूप से 20 किलोवाट तक बढ़ाया जा चुका था.

अप्रैल, मई और जून में भार वृद्धि की स्थिति की जानकारी मासिक बिलिंग और मास्टर डाटा के माध्यम से बाद में प्राप्त होती है. नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अगले माह उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही की जा सकती है. ऐसी स्थिति में जुलाई से पूर्व बढ़े हुए भार के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी ठहराना नियम सम्मत नहीं है.

समिति के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि विद्युत वितरण निगम की जिम्मेदारी उपभोक्ता को विधिवत कनेक्शन उपलब्ध कराना और निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है. भवन के अंदर की वायरिंग, विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता, विद्युत सुरक्षा प्रमाणन, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन और समय-समय पर सुरक्षा परीक्षण की जिम्मेदारी भवन स्वामी और संबंधित नियामक व सुरक्षा एजेंसियों की होती है.

इन दायित्वों की उपेक्षा कर एक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करना वास्तविक तथ्यों से ध्यान हटाने का प्रयास है. किसी भी दुर्घटना की निष्पक्ष और तकनीकी जांच पूरी होने से पूर्व दंडात्मक कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम

उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिख रही है। पार्टी ने जिस तरह ब्रा१ाण, पिछड़ा, दलित और अलग-अलग इलाकों से जुड़े चेहरों को जगह दी है, उससे यह संदेश दिया जा रहा है कि संगठन केवल एक वर्ग या एक क्षेत्र के सहारे नहीं चलेगा, बल्कि हर बड़े सामाजिक समूह को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि नई टीम के गठन में प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद रणनीतिकार सुनील बंसल की छाप नजर आती है। यही वजह है कि इसे सिर्फ संगठनात्मक पेरबदल नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कवायद भी माना जा रहा है। भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में जीत सिर्फ नारे से नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और बूथ स्तर की पकड़ से तय होती है। जनसाधारण के नजरिये से देखें तो पार्टी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को भी गंभीरता से लेने की कोशिश की है। नई टीम में इस वर्ग को अपेक्षावृत अच्छी जगह देकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी एक सामाजिक आधार को कमजोर नहीं होने देगी। इससे यह भी माना जा रहा है कि पार्टी पुराने भरोसेमंद मतदाताओं को फिर से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि चुनाव के समय संगठन का यह संतुलन बहुत मायने रखता है।सूत्रों और राजनीतिक चचाओं में यह बात भी उठ रही है कि सुनील बंसल की भूमिका अब भी उतनी ही अहम है, जितनी पहले थी। वे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को गहराई से समझते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी रणनीति की बड़ी भूमिका मानी गई थी। इसीलिए नई टीम को देखकर बहुत से लोग इसे उसी पुराने संगठनात्मक मॉडल की वापसी के रूप में देख रहे हैं, जिसमें नीचे तक पकड़, सामाजिक गणित और लगातार संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी संदर्भ में संदीप बंसल का नाम भी चर्चा में आ रहा है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वे भी प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसका कारण यह है कि भाजपा अब ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है जो संगठन, वर्ग- संतुलन और चुनावी प्रबंधन तीनों में काम आ सवें। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ी, तो संदीप बंसल जैसे नेताओं की उपयोगिता और बढ़ सकती है।नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जा रही है कि उसमें केवल चेहरों का नहीं, बल्कि संदेशों का भी संतुलन साधा गया है। एक तरफ पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह सभी बड़े समाजों को साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ यह भरोसा भी देना चाहती है कि चुनावी प्रबंधन पहले की तरह मजबूत हाथों में है। जनता के बीच भी यही धारणा बनती है कि भाजपा संगठन को हल्के में नहीं लेती और हर बड़े चुनाव से पहले अपनी व्यवस्था को फिर से कसती है। खैर, उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को खास तौर पर साधने की कोशिश दिखाई दी है। पार्टी ने 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों के साथ पूरी कार्यकारिणी को नए सिरे से सजा दिया है, जिसमें ब्रा१ाण, पिछड़ा, दलित, पूर्वाचल, पमिमी यूपी और अवधकानपुर जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ध्यान से रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिह, डॉ. धर्मेंद्र सिह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दरुविजय शाक्य, रमेश सिह, नीरज सिह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिह, डॉ. वृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, वृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिह, डॉ. धर्मेंद्र सिह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दरुविजय शाक्य, रमेश सिह, नीरज सिह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिह, डॉ. वृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, वृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता जैसे नाम अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का संदेश देते हैं. प्रदेश महामंत्रियों में रामप्रताप सिह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जगह मिली है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पहली बार 28-29 जून को दिल्ली में होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 और 29 जून को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जहां गांवों के समग्र विकास, प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के तेज, समावेशी और सतत विकास को नई दिशा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मंथन करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पहली बार व्यापक रूप से आयोजित इस राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन-2026 में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए गांवों के विकास के लिए साझा रणनीति तैयार की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'विकसित ग्राम, विकसित भारत' के विजन को जमीन पर उतारना है। इसके तहत विकसित भारत- जी राम जी (VB-GRAM-G) अधिनियम-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की बेहतर योजना-निर्माण प्रक्रिया और संसाधनों के कुशल उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री होंगे शामिल

इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति-निमार्ताओं और विभिन्न योजनाओं से जुड़े विशेषज्ञों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस राष्ट्रीय मंथन में राज्यों के अनुभव, नवाचार और जमीनी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा होगी, जिससे नीतिगत स्तर पर मजबूत और व्यावहारिक समाधान सामने आ सकें।

थीमैटिक सत्र और बेस्ट प्रैक्टिस पर फोकस

शिवराज सिंह ने कहा कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न थीमैटिक और ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण आवास, सड़क कनेक्टिविटी, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। राज्यों द्वारा अपनाई गई सफल पहल और नवाचारों को साझा किया जाएगा, ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि 'लखपति दीदी' पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और बाजार से जुड़ाव पर भी फोकस रहेगा।

तकनीक और अक के उपयोग पर जोर

श्री चौहान ने बताया कि सम्मेलन में ग्रामीण विकास योजनाओं में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को विशेष महत्व दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए विभिन्न तकनीकी समाधानों पर चर्चा की जाएगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और प्रभावशीलता लाई जा सके।

तय होगी आगे की दिशा

शिवराज सिंह ने बताया कि सम्मेलन के दूसरे दिन 29 जून को प्लेनरी सत्रों और मंत्रिस्तरीय चचाओं के माध्यम से सभी राज्यों के सुझाव लिए जाएंगे और भविष्य की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह समापन सत्र में सम्मेलन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में गांवों की केंद्रीय भूमिका पर अपनी बात रखेंगे।

ग्रामीण भारत के लिए नए संकल्प और ठोस कार्ययोजना

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन केवल समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए नए संकल्प और ठोस कार्ययोजना तय करने का अवसर है, जिससे देश के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

महत्वपूर्ण प्रकाशनों का होगा विमोचन

सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन भी किया जाएगा। इनमें जल सुरक्षा, ग्राम विकास योजना, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और सफलता की कहानियों से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे, जो राज्यों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे।

'नए एफसीआरए नियम सिविल सोसायटी पर सुनियोजित हमला': कांग्रेस का पीएम मोदी को खत

(जीएनएस)।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 विकास और कल्याण कार्य करने वाले NGO और अल्पसंख्यक संस्थानों का गला घोंटने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने नये नियम को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

कांग्रेस ने विदेशी चंदा नियमन यानी एफसीआरए के नियमों में हाल में किए गए बदलावों को सिविल सोसायटी पर सुनियोजित हमला करार दिया है। इसने कहा है कि यह एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थानों का गला घोंटने की कोशिश है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि नए एफसीआरए नियम को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इन नियमों के जरिए गैर-सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

क्या हैं नए FCRA नियम?

गृह मंत्रालय ने हाल ही में ऋछफ्ख नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत विदेशी फंड पाने वाले संगठनों को अपने काम के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को सरकार द्वारा तय की गई सूची में से चुनना होगा। इसके अलावा किसी संस्था के प्रमुख पदों पर यदि भारतीय मूल के अलावा अन्य विदेशी नागरिक हैं तो सामान्य परिस्थितियों में उसे न तो विदेशी फंड पाने की अनुमति दी जाएगी और न ही पंजीकरण होने दिया जाएगा। सरकार ने कुछ धार्मिक और आस्था आधारित गतिविधियों को अनुमति दी है, लेकिन धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को कई श्रेणियों से बाहर रखा गया है।

कांग्रेस ने क्या आपत्ति जताई?

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि ये नियम किसी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों को नियंत्रित और कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने लिखा कि सरकार एनजीओ को एक तयशुदा सूची से काम या गतिविधियाँ चुनने और सीमित क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर कर रही है। इससे संस्थाओं का वह लचीलापन खत्म हो जाएगा, जिसके जरिए वे आपदा, सामाजिक संकट या स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करती हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अलग-अलग राज्यों या अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अलग शुल्क लगाना सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं पर 'प्रशासनिक टैक्स' थोपने जैसा है।

छोटे संगठनों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

वेणुगोपाल का कहना है कि नए नियमों में छोटी प्रशासनिक गलतियों पर भी भारी जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जुमार्ना फंड की 30 प्रतिशत राशि या न्यूनतम एक लाख रुपये तक हो सकता है। इससे छोटे और जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित होंगे।

कांग्रेस का दावा है कि बड़ी संस्थाओं के पास कानूनी और प्रशासनिक संसाधन होते हैं, लेकिन गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे संगठन ऐसे नियमों का सामना नहीं कर पाएंगे।

सोशल मीडिया की जानकारी क्यों मांगी?

कांग्रेस ने नियमों में सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट और प्रकाशित सामग्री की जानकारी अनिवार्य रूप से देने के प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है। वेणुगोपाल ने इसे 'निगरानी की मानसिकता' बताया और कहा कि इससे नागरिक संगठनों की गतिविधियों पर अनावश्यक नियंत्रण बढ़ेगा। उनका आरोप है कि सरकार सामाजिक संगठनों की निगरानी करने और उन्हें दबाव में रखने की कोशिश कर रही है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को लेकर भी चिंता

कांग्रेस ने कहा कि नए नियमों का असर विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित संस्थाओं पर पड़ सकता है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली अनेक संस्थाएं पहले से ही ऋछफ्ख जुड़े सख्त नियमों का सामना कर रही हैं और नए संशोधन उनके कामकाज को और मुश्किल बना देंगे।

पहले भी हजारों लाइसेंस रद्द हुए

पत्र में कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में ऋछफ्ख का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है और हजारों संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उनके अनुसार, इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सहायता से जुड़े कई कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिलता था। उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में स्वतंत्र और मजबूत सिविल सोसायटी की जरूरत होती है, न कि ऐसी संस्थाओं की जो सरकारी दबाव में काम करें।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पहले संसद में ऋछफ्ख संशोधन लाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब उन्हीं बदलावों को नियमों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इससे संसद में व्यापक चर्चा और लोकतांत्रिक बहस की प्रक्रिया कमजोर होती है।

सरकार की मंशा पर सवाल

कांग्रेस का आरोप है कि नए नियमों का मकसद सामाजिक संगठनों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर करना है। पार्टी ने इन्हें कठोर और दमनकारी कदम बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है।

शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकियों का जमावड़ा, कंधे पर हाथ रखे दिखे दहशतगर्द

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जून 2026 के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में हुए इस जनाजे में खेल और राजनीति से जुड़े कई बड़े लोग पहुंचे थे। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के दहशतगर्दों को भी वहां मौजूद देखा गया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद

यह मामला तब सामने आया, जब इस्लामाबाद के एच-8 कब्रिस्तान में हुए नमाज-ए-जनाजा के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। इन वीडियो में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग आराम से घूमते और शोएब अख्तर के परिवार के सदस्यों से मिलते-जुलते नजर आए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इन तस्वीरों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई।

डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा और उसके राजनीतिक दल PMML के आधिकारिक मीडिया विंग ने खुद इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में PMML के इस्लामाबाद अध्यक्ष इनाम उर रहमान कम्बोह अपने सहयोगियों के साथ दिखाई दिए। उन्हें शोएब अख्तर के परिवार से गले मिलकर सांत्वना देते हुए भी देखा गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के निजी पारिवारिक कार्यक्रम तक इतनी आसानी से पहुंच कैसे मिली।

लश्कर और PMML के रिश्ते क्यों हैं चर्चा में?

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है। कई विशेषज्ञ इसे मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नेटवर्क से जुड़ा राजनीतिक मंच है। उनका दावा है कि जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगने के बाद इस नेटवर्क ने राजनीतिक पहचान के साथ काम करना शुरू किया। इनाम उर रहमान कम्बोह को भी इसी संगठन का प्रमुख चेहरा माना जाता है।

अब तक शोएब अख्तर ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद पर फिलहाल शोएब अख्तर या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं, वैश्विक सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को प्रतिबंधित संगठनों द्वारा मुख्यधारा के कार्यक्रमों के जरिए खुद को सामान्य और स्वीकार्य दिखाने की कोशिश के रूप में देख रही हैं। आने वाले दिनों में यह मामला पाकिस्तान की राजनीति, सुरक्षा और खेल जगत में चर्चा का बड़ा विषय बना रह सकता है।

लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 300 पार होते ही इण्डिया गठबंधन में बेचैनी? अब इस पार्टी को मनाने में जुटे विपक्षी

(जीएनएस)।

लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बढ़ती ताकत ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 293 सीटें थीं, वह अब सहयोगियों की मदद से तेजी से बढ़ते हुए 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। एनडीए के इस बढ़ते कुनबे ने विपक्षी खेमे यानी क्ठऊक्रअ गठबंधन की नींद उड़ा दी है।

विपक्षी खेमे में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता अपने पुराने और मजबूत साथी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (उ्टङ) को बचाए रखने की है, जो फिलहाल कुछ नाराज दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि संसद में बदलते समीकरणों के बीच इंडिया गठबंधन अपने पुराने सहयोगी की नाराजगी दूर करने में जुट गया है।

विपक्षी खेमे में मची इस खलबली के पीछे असली वजह सीटों का गणित है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों ने एक अलग गुट 'नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' बनाकर ठऊअ को अपना समर्थन दे दिया, जिससे आंकड़ा सीधे 313 पर पहुंच गया। इसके ठीक बाद उद्धव ठाकरे गुट के 6 और सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट के साथ आ गए, जिससे एनडीए की ताकत 319 तक जा पहुंची।

अब अगर लोकसभा में 22 सांसदों वाली उ्टङ भी मुद्दों के आधार पर सरकार का साथ देती है, तो यह संख्या 341 हो जाएगी। संसद के निचले सदन में दो तिहाई बहुमत के लिए वैसे तो 362 सीटें चाहिए, लेकिन 3 सीटें खाली होने की वजह से यह जादुई आंकड़ा फिलहाल 360 का है। बजट सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सरकार को 298 सांसदों का साथ मिला था, जो जरूरी आंकड़े से 62 कम था। यही वजह है कि एनडीए अब नए साथियों को जोड़ने में लगा है।

इस पूरे फेरबदल के बीच डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन के एक बयान ने क्ठऊक्रअ गठबंधन को भारी टेंशन में डाल दिया है। स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी चुनावी गठबंधन की जरूरतों को लेकर नए सिरे से विचार करेगी। इसके बाद से ही कांग्रेस और विपक्ष के बाकी बड़े नेता डीएमके को मनाने में जुट गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी को आखिर पहले टी-20 में क्यों नहीं मिला मौका? कप्तान अय्यर ने बताई बड़ी वजह

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े डेब्यू का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है।

इसके चलते महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब वैभव को रविवार (28 जून) को होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले तक का इंतजार करना होगा। हाल ही में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सीनियर टीम के नियमित कॉम्बिनेशन और स्थापित खिलाड़ियों को बिना किसी ठोस तकनीकी कारण के टीम से बाहर करना ड्रेसिंग रूम के संतुलन को प्रभावित कर सकता था। यही कारण है कि चयनकताओं और टीम प्रबंधन ने पहले मुकाबले में जल्दबाजी करने के बजाय अनुभव को तरजीह दी।

शुक्रवार को टॉस के दौरान जब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से वैभव सूर्यवंशी के खेलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। कप्तान अय्यर ने कहा कि वैभव एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे आज नहीं खेल रहे हैं। हमारे पास स्क्वॉड में जबरदस्त अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछली कुछ सीरीज में भारत के लिए अद्भुत प्रदर्शन किया है।

सही समय पर मिलेगा मौका

अय्यर ने आगे भरोसा देते हुए कहा कि हम उन खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं जो लगातार शानदार काम कर रहे हैं। वैभव को सही समय आने पर निश्चित रूप से खेलने का अवसर मिलेगा। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। वैभव अभी महज 15 वर्ष के हैं।

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दी थी ये दलील

मैच से पहले भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी वैभव की प्रतिभा की जमकर तारीफ की थी, लेकिन किसी स्थापित खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी न करने की बात कही थी। कोटक ने कहा था कि सिर्फ किसी नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए उस खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना जो पहले से रन बना रहा है सही नहीं होगा। हमें एक बहुत ही बारीक रेखा का ध्यान रखना होता है।

पाकिस्तान : सैनिटरी पैड्स और टैम्पोन खत्म, फिर भी काफी महंगा! फूड या पैड्स में से एक ही नसीब, भारत में क्या है हाल?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सैनिटरी पैड्स और टैम्पोन पर लगने वाला 18 फीसदी सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा जरूरी कदम है। हालांकि इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ टैक्स हटाने से उन लाखों-करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी, जो आर्थिक तंगी की वजह से आज भी सैनिटरी पैड्स खरीद नहीं पातीं? जानेंगे पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा और पीरियड पॉवर्टी का हाल।

यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे सामाजिक कार्यकताओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों का लंबा संघर्ष रहा। लाहौर हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका भी दायर की गई थी। 'विमेन ऑफ द ईयर' महनूर उमर और अहसान जहांगीर खान ने मांग की थी कि सैनिटरी पैड्स को एक जरूरी स्वास्थ्य उत्पाद माना जाए। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार इन उत्पादों से 18 फीसदी सेल्स टैक्स हटाने का फैसला लिया।

टैक्स हटाना अच्छी शुरूआत जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में पीरियड पॉवर्टी यानी माहवारी से जुड़ी गरीबी की स्थिति बेहद गंभीर है। यूनिसेफ (वठकउएऋ) के मुताबिक, पाकिस्तान में पीरियड्स वाली सिर्फ 12 फीसदी महिलाएं ही ब्रांडेड सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर पाती हैं। यानी करीब 88 फीसदी महिलाएं और लड़कियां आज भी पुराने कपड़ों या असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी, जागरूकता की कमी और सामाजिक रूढ़ियां हैं।

पाकिस्तान में माहवारी को लेकर जागरूकता की कमी का असर लड़कियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, हर पांच में से एक लड़की पीरियड्स के दौरान स्कूल जाना छोड़ देती है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं, जहां न साफ शौचालय हैं और न ही सैनिटरी नैपकिन आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में सिर्फ टैक्स हटाने से यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली।

विशेषज्ञों का कहना है कि 18 फीसदी सेल्स टैक्स हटने से कीमतों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे सैनिटरी पैड्स सभी महिलाओं की पहुंच में नहीं आ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पैड्स और उनके कच्चे माल पर कुल टैक्स का बोझ अब भी करीब 40 फीसदी है। जब तक सरकार बाकी टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी में भी कटौती नहीं करेगी, तब तक कीमतों में बड़ी कमी आना मुश्किल है।

पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान जैसे गरीब इलाकों में एक मां को अपनी तीन बेटियों के लिए हर महीने करीब 40 अमेरिकी डॉलर सिर्फ सैनिटरी पैड्स पर खर्च करने पड़ते हैं। वहीं पाकिस्तान में एक परिवार की औसत मासिक आय करीब 140 अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में कई परिवारों के सामने राशन खरीदें या सैनिटरी पैड्स, जैसी मजबूरी खड़ी हो जाती है।

सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि समाज की सोच भी बड़ी समस्या है। बलूचिस्तान के क्वेटा और मस्तुंग जैसे इलाकों में कई लड़कियां मेडिकल स्टोर से पैड्स खरीदने में शर्म महसूस करती हैं। वे दुकान खाली होने का इंतजार करती हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले।

लखनऊ अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर में बड़ी कार्रवाई, होटल-कोचिंग-लाइब्रेरी समेत 24 संस्थान सील, 35 को नोटिस

बेसमेंट में संचालित संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी से छात्रों को निकालने के बाद लगाया गया ताला.

(जीएनएस)।

मुजफ्फरनगर : लखनऊ में हुए हृदयविदारक अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त हो गया है. जिलेभर में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, नर्सिंग होम, होटल और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई की जा रही है.

मुजफ्फरनगर में फायर सेफ्टी और भवन सुरक्षा मानकों की जांच के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों

द्वारा जिले में संचालित कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, नर्सिंग होम, होटल, बैंक्विट हॉल और अन्य सार्वजनिक संस्थानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर कुल 24 संस्थानों को सील किया जा चुका है. इनमें कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, नर्सिंग होम, होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. इसके अलावा 35 संस्थानों में कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी कर निर्धारित समय में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.

अभियान के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है. विशेष रूप से बेसमेंट में संचालित संस्थानों और फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, उन्हें बंद कराया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार जिन कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी में विद्यार्थी मौजूद थे. उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर संचालन बंद कराया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

केंद्र के किस फैसले से परेशान हुए तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय? पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बोले- आप...

सीएम जोसेफ विजय ने कहा कि यह मुद्दा तमिलनाडु के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठछ्उ इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना, विकास और नियमित संचालन के जरिए हमारे राज्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है.

(जीएनएस)।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार (26 जून, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में सीएम विजय ने केंद्र सरकार की तरफ से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLC) में अपने हिस्सेदारी (इक्विटी) के प्रस्तावित विनिवेश (डिसइंवेस्टमेंट) की प्रक्रिया को आगे बढ़ने के फैसले का विरोध किया है. इसके साथ ही, उन्होंने पीएम मोदी से केंद्र सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है.

पीएम मोदी को लिखे पत्र में क्या बोले सीएम विजय?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा, 'मैं भारत

सरकार की तरफ से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLC) में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश को आगे बढ़ाने के फैसले पर तमिलनाडु सरकार की गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं, जिसमें अधिसूचना के मुताबिक पेड-अप इक्विटी का अधिकतम 3 प्रतिशत हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा जाना प्रस्तावित है, इसमें 2 प्रतिशत का बेस ऑफर और अतिरिक्त एक प्रतिशत का ग्रीन-शू ऑप्शन शामिल है.'

उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु सरकार भारत सरकार की तरफ से ठछ्उ इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को और कम करने का कड़ा विरोध करती है. यह मुद्दा तमिलनाडु के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठछ्उ इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना, विकास और नियमित संचालन के जरिए हमारे राज्य से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है.'

ये सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी नहीं, रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है- विजय

CM जोसेफ विजय ने कहा, 'तमिलनाडु सरकार का मत है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा, मिनरल विकास और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति (एसेट) है. भारत सरकार की हिस्सेदारी में किसी भी तरह की कमी ऐसे रणनीतिक महत्व वाले सार्वजनिक इंटरप्राइज में सरकारी स्वामित्व के संबंध में एक अवांछनीय मिसाल कायम करेगी.'

उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे इस कदम से चिंताएं न सिर्फ वित्तीय पहलुओं तक सीमित है, बल्कि यह राज्य, उसके नागरिकों और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के हितों से भी जुडा हुआ विषय है.' उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरी यकीन है कि भारत सरकार तमिलनाडु सरकार की तरफ से उठाई गई इन चिंताओं पर गंभीरता से विचार करेगी.

लखनऊ के होटल संचालकों को FIRE SAFTY टिप्स, कहां रखे सिलेंडर, कैसे कराएं वायरिंग?

अलीगंज अग्निकांड घटना के बाद अब ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पर जोर.

(जीएनएस)।

लखनऊः अलीगंज अग्निकांड घटना के बाद अब संबंधित विभाग शिथिलता छोड़ पूरी तरह गंभीरता बरत रहे हैं. नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए प्रयास करने में लग गए हैं. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने जहां बिल्डिंग में बिना विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी के कनेक्शन देने पर सख्त पाबंदी लगा दी है तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण भी होटल संचालकों से नियमों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है. जागरूकता के लिए एलडीए की तरफ से होटल संचालकों के साथ बैठककर उन्हें नियम कानून समझाए जा रहे हैं.

एलडीए ने शुरू किया अभियानः लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से शहर में बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जागरूकता और मॉनिटरिंग अभियान संचालित किया जा रहा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से संबंधित संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए होटल संचालकों के

साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के प्लूटो सभागार में गुरुवार को हुई बैठक में एलडीए, अग्निशमन विभाग, ऊर्जा विभाग समेत अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक मानकों और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इस मौके पर एलडीए न प्रेजेंटेशन के माध्यम से होटल संचालन में अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों को स्पष्ट किया गया.

क्या खास टिप्स दिए गएः बैठक में विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि किचन में इस्तेमाल किये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों को सीढ़ियों, बेसमेंट या संकुचित स्थानों पर न रखा जाए. एयर कंडीशन सर्किट पर अतिरिक्त विद्युत भार न डाला जाए और जनरेटर के साथ ही बैटरियों को उचित वेंटिलेशन वाली जगहों पर स्थापित किया जाए. यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि सभी भवनों में आपातकालीन निकास अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों उनमें किसी प्रकार की बाधा न हो. विद्युत सुरक्षा को लेकर बताया गया कि सभी संस्थानों में मानक गुणवत्ता की वायरिंग और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके. बैठक के दौरान अग्निशमन विभाग से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया. उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया.

होटल संचालकों से अपीलः एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने होटल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्धारित मानकों का हरहाल में पालन सुनिश्चित कराया जाए. इसमें किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि अब एलडीए ने भवन स्वीकृति से पूर्व सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए नोटरीकृत शपथपत्र अनिवार्य किया है, साथ ही जिन भवनों में फायर एनओसी आवश्यक नहीं है वहां भी न्यूनतम मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए शपथपत्रों का अभिलेखीकरण व साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. उन्होंने बताया कि अगले

16वीं भारत-जापान वार्षिक बैठक : जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची आएंगी भारत, पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 1-3 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगी। यह समिट दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने और मजबूत करने के साथ-साथ परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर देगा।

यह प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2025 में जापान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वे 15वें भारत-जापान सालाना समिट में शामिल हुए। यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव में जीत पर जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल

पार्टनरशिप दुनिया भर में शांति, स्थिरता और खुशहाली बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि ताकाइची की काबिल लीडरशिप भारत-जापान दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2025 में टोक्यो में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भारत-जापान आर्थिक मंच कार्यक्रम के दौरान शीर्ष उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए पांच-पॉइंट रोडमैप पेश किया।उन्होंने कहा अभी भारत-जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

दो दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो और जापानी सांसदों के एक समूह के साथ एक बैठक की। इस दौरान भारत और जापान के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, उन्होंने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने से संबंधित कई समझौते पर मुहर लगी।

पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ मियागी प्रांत के सेंडाई शहर का दौरा किया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड (टीईएल मियागी) का दौरा किया। कारखाने में उन्हें टीईएल की वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भूमिका, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भारत के साथ वर्तमान व भविष्य के सहयोग के बारे में जानकारी दी गई थी।

अयोध्या कांड पर एक्शन, विपक्ष पर निशाना; क्या सीएम योगी ने राम मंदिर को बनाया यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा

अयोध्या चोरी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया है। देवरिया के कार्यक्रम से सीएम योगी ने चुनावी मैदान में मुद्दे को उठाए जाने के संकेत दे दिए हैं।

देवरियाः उत्तर प्रदेश के राम मंदिर दान चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से तेजी से एक्शन एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। दान की राशि में चोरी का मामला गंभीर था। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। सरकार ने मामले की जांच कराने के बाद एक्शन शुरू कर दिया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कवायद शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की बात कर सीएम योगी ने सीधे तौर पर विपक्ष और अयोध्या राम मंदिर के संबंधों को सामने ला दिया है। वहीं, राम मंदिर के प्रति सरकार और अपनी पार्टी की मंशा को साफ करते हुए बड़े और कड़े सवाल शुरू किए हैं।

मामले में अब तक क्या?

राम मंदिर में दान चोरी का मामला गरमाते ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया गया। सीएम योगी ने पत्र मिलते ही इसी दिन तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। 15 जून से एसआईटी की जांच शुरू हुई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून को सरकार को सौंपी। इसमें दान में चोरी और प्रक्रिया में गड़बड़ी के संकेत मिले।

एसआईटी की ओर से दी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मामले में एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की गई। सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से केस दर्ज कराया गया है। गिरफ्तारी हो गई है। जांच शुरू होने के 10 दिनों के भीतर एक्शन ने सरकार को मुद्दे में बढ़त दिलाई है।

इंल्लॅ"ीरँ ढ१ङ्ग३ी२३ः भगवान राम की मूर्ति से जुड़े विवाद में हिंदुओं का तारिक सरकार को कैसा अल्टीमेटम

सीएम ने ऐसे बोला हमला

देवरिया में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। राम मंदिर आंदोलन काल का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक पक्ष

कहता था कि राम हैं ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये लोग नकारना चाहते थे। लगातार कोर्ट में मुकदमा लड़ते रहे। वकीलों की फौज राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ी करते रहे।

दूसरा पक्ष वो है जो जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाते थे। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे तुम हमें आस्था बताओगे? सीएम योगी ने इस बयान के जरिए विपक्षी गठबंधन को घेरने की कोशिश की।

सीएम का निशाना कहां?

सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर विपक्ष को राम मंदिर मुद्दे के मामले में फंसाने की कोशिश में जुटे हैं।

विपक्ष की ओर से राम मंदिर का मुद्दा उठाए जाने से इसको लोगों तक ले जाने में भाजपा कामयाब होगी।

राम मंदिर के मुद्दे के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्माण की चर्चा में जुट गए हैं।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में तेजी से एक्शन के जरिए योगी सरकार ने गड़बड़ी पर सख्त एक्शन के दावों को पुख्ता किया है।

आरोप लगाने वालों को एसआईटी के समक्ष सबूत पेश करने की चुनौती देकर गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया गया है।

सीएम योगी अब कांग्रेस के भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए जाने वाले सवालों पर निशाना साधा है। कांग्रेस खेमे के वकीलों का भी मामला उठाया है, जो राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाए जाने का मुद्दा उठाया है।

अखिलेश यादव के शासन के दौरान राम मंदिर मुद्दे पर कानूनी लड़ाई को धीमा करने का मामला भी उठा रहे हैं।

राम मंदिर के मुद्दे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ सपा के पीडीए पॉलिटिक्स की जगह हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ फोकस बढ़ाते दिख रहे हैं।

हिंदू पर्वों का किया जिक्र

सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान पिछली सरकारों में हिंदू पर्वों के दौरान की स्थिति का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि राम नवमी पर दंगा करवाते थे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को प्रतिबंधित करते थे। कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे। दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। याद कीजिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोंचा था। बेइमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे और वे लोग आज अयोध्या पर आक्षेप लगा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सभी के सामने आएगा। लेकिन, मैं फिर से अपील करूंगा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। अगर तथ्य या प्रमाण नहीं है तो आरोप-प्रत्यारोप बंद करो। प्रमाण हैं तो रक्ळ के सामने पेश करो।

सीएम बनाएंगे मौका?

सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर प्रकरण को क्या एक मौका बना लेंगे? क्या यूपी चुनाव 2022 में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने 'बुलडोजर बाबा' कहकर उन्हें एक बड़ा चुनावी स्लोगन दे दिया था, क्या यूपी चुनाव 2027 में राम मंदिर का मुद्दा उसी प्रकार का 'चुनावी गिफ्ट' साबित होगा? ये सवाल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसका कारण है, राम मंदिर का पिछले चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाना।

'जनता अब भाजपाइयों का भाषण सुनने के मूड में नहीं', लखनऊ अग्निकांड और वायरल वीडियो पर बरसे अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, एक 'म्यूट वीडियो' और उनके 'हृदयहीन' व्यवहार का जिक्र किया।

(जीएनएस)।

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने एक्स पर एक समाचार चैनल की क्लिप साझा करते हुए लिखा, जनता अब भाजपाइयों का भाषण सुनने के मूड में नहीं है। जो दूर से ये धारणा बनाए बैठे थे कि 'कोई' ईमानदार है। भ्रष्ट नहीं है। जनसेवा में निस्वार्थ भाव से लगा है। भौतिक-लालच से परे है, अब तथाकथित माननीय का 'म्यूट कर दिया गया वो वीडियो' देखकर, उनका भी सारा भ्रम टूटकर चकनाचूर हो गया है।

सपा प्रमुख ने आगे लिखा, जो व्यक्ति सैकड़ों कैमरों के सामने किसी मां की गोद उजड़ जाने के सबसे बड़े दुख के क्षण में भी सांत्वना देने की जगह धमकी भरे लहजे में, अपने कठोर हाव-भाव के साथ बोल रहा हो, वो कितना हृदयहीन, संवेदना शून्य होगा, अब ये बात सबके सामने खुल गई है। अब इनके झूठे नायकत्व का सारा मायाजाल तार-तार हो गया है।

सबसे ज्यादा ठेस इनके उन समर्थकों को लगी है, जो इनकी 'मिथ्या दिव्यता' के गुणगान करते नहीं थकते थे। अब क्या तथाकथित माननीय ये कहेंगे कि उनका वीडियो एआइ जेनरेटेड है। अगर जनता चाहे तो एआइ से होंठों को पढ़कर ये बता सकती है कि 'वास्तव में उन्होंने किन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था'। जिसका अपने वचन-व्यवहार पर नियंत्रण नहीं वो प्रदेश पर क्या नियंत्रण करेगा और दिल्ली पर राज के सपने क्या देखेगा।

लखनऊ अग्निकांड के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार 'कोचिंग बंदी' ले आई। माना सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए लेकिन क्या पिछले 10 साल से सरकार सो रही थी। सच्चाई ये है कि अब सुरक्षा मानकों और अनुमति आदि के नाम पर करोड़ों की उगाही का खेल शुरू हो गया है। भाजपाई आपदा में संपदा ढूंढ लेते हैं।

109 मंजिला इमारत में घुसा विमान, 9/11 की यादें हुई ताजा, आतंकी हमला या हादसा?

(जीएनएस)।

चीन की राजधानी बीजिंग से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार, 26 जून 2026 की दोपहर एक छोटा नागरिक विमान बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत सीआईटीआईसी टावर (ङ्खँल्ल ४ल्ल) से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि इमारत के बाहरी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा और विमान के टुकड़े नीचे सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

9/11 हमले की यादें हुई ताजा

हादसे के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आ गया। सुरक्षा को देखते हुए पूरी इमारत खाली करा ली गई और उसके आसपास का इलाका सील कर दिया गया। पुलिस, दमकल और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने अभी तक विमान में सवार लोगों या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस घटना ने अमेरिका के 9/11 की यादें

ताजा कर दी हैं।

शुरूआती जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त विमान चीन में बना बी-12पीपी मॉडल का एक हल्का नागरिक विमान था। चीनी मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में केवल एक पायलट सवार था। इस विमान ने बीजिंग के शिफोसी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, विमान को उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद शाम लगभग 5:40 बजे वापस एयरपोर्ट लौटना था। लेकिन तय समय से पहले ही विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया और बीजिंग के ईस्ट फिफ्थ रिंग रोड के पास उसका रडार से संपर्क टूट गया। इसके बाद उससे दोबारा संपर्क नहीं हो सका।

कैसे हुआ हादसा? जांच शुरू

बीजिंग जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में किसी छोटे विमान का रास्ता भटककर सीधे सबसे ऊंची इमारत से टकराना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उड्डयन विशेषज्ञ और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर इसमें मानवीय गलती थी। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।